(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार लापरवाही और अकुशलता के कारण वहां होने वाले गबन और घोटालों इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निगम में गबन, भ्रष्टाचार, लापरवाही और अक्षमता से संबंधित मामलों पर रोक लगाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और सरकार दोनों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

सतर्कता संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय स्तर पर सचिव (खाद्य और नागरिक पूर्ति) की अध्यक्षता में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। आंतरिक समीक्षा करने के पश्चात् कमियों की गणना और सूचना देने संबंधी संशोधित प्रक्रिया अपनाई गई है जिला कार्यालयों का अधिक बार निरीक्षण किया जाता है।

गबन, भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने और आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए सतर्कता तंत्र को सक्रिय बनाया गया है।

चीनी का आयात

1453. **श्री डी०पी० यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत ने विदेशों से कुल कितनी चीनी आयात की है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में प्रचुर चीनी भंडार होते हुए भी ओ०जी०एल० के अंतर्गत पांच प्रतिशत सीमा शुल्क और 850/- रुपये प्रति मीटरी टन की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी पर चीनी का आयात होने के कारण चीनी उद्योग के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 3.30 लाख टन चीनी का आयात हुआ।

(ख) और (ग) चीनी मौसम 1997-98 (अक्तूबर से सितम्बर) के आरंभ में 66.00 लाख टन चीनी का अथशेष स्टाक था और चीनी मौसम 1997-98 के दौरान 128.30 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि चीनी की अनुमानित खपत 139.8 लाख टन थी। चीनी मौसम 1997-98 में 6.96 लाख टन चीनी अनंतिम रूप से आयात होने का अनुमान लगाया गया था जो कि चीनी मौसम 1997-98 में हुए चीनी के उत्पादन का मात्र 5.43% है। चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों अर्थात् इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि चीनी का अत्यधिक आयात हो रहा है और उन्होंने चीनी के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने की मांग की है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

Transfer Policy for Ayurvedic Doctors in Delhi

1454. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any transfer policy of Government with regard to Ayurvedic doctors in Delhi;

(b) the details of doctors posted in Delhi, CGHS Ayurvedic Dispensary-wise, wtih the dates of their posting in that dispensary;

(c) whether some doctors are being transferred frequently without any reasons thereby causing harassment to them;

(d) whether Ayurvedic doctors in Delhi are detailed to the rotational month–wise duty; if so, whether the same practice is being followed in respect of Homoeopathic, Siddha, Unani, etc; and

(e) if not, the reasons for detailing as above in case of Ayurvedic doctors only?